**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं0 1086**

**दिनांक 19 दिसम्‍बर, 2018**

**पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में प्रतिदिन संशोधन किया जाना**

**1086. श्री अब्दुल वहाबः**

**कुमारी शैलजाः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं साथ ही कीमतों को स्थिर करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ख) क्या जब अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती हैं तो पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्यनिर्धारण प्रणाली को विनियंत्रित करना केवल एक परिपाटी है; और

(ग) अमरीका द्वारा हाल ही में ईरान पर लगाये गए प्रतिबंधों को देखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किये गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

1. से (ग) : सरकार ने पेट्रोल और डीजल के मूल्‍यों को क्रमश: दिनांक 26.06.2010 और 19.10.2014 से बाजार निर्धारित बना दिया है। तब से, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कं‍पनियां (ओएमसीज) अंतर्राष्‍ट्रीय उत्पाद मूल्‍यों तथा अन्‍य बाजार दशाओं के अनुसार पेट्रोल और डीजल के मूल्‍य निर्धारण के संबंध में उपयुक्‍त निर्णय लेती हैं। ओएमसीज ने मूल्‍यों को केवल बढ़ाया ही नहीं है अपितु तदनुसार घटाया भी है। सरकार राजसहायता प्राप्‍त घरेलू एलपीजी के ग्राहकों के लिए प्रभावी मूल्‍य और पीडीएस मिट्टी तेल के खुदरा बिक्री मूल्‍य को आवश्‍यकतानुसार घटाती-बढ़ाती रहती है।

 पेट्रोल और डीजल के मूल्‍य को कम करने और उपभोक्‍ताओं को राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने दिनांक 04 अक्‍तूबर, 2017 से पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की थी। केंद्र सरकार ने दिनांक 05 अक्‍तूबर, 2018 से पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क में 1.50 रुपए प्रति लीटर की और कमी कर दी है और सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज ने भी पेट्रोल और डीजल के समग्र मूल्‍य को 1.00 रुपए प्रति लीटर कम कर दिया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से भी उनके द्वारा पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए वैट में 2.50 रुपए प्रति लीटर की कमी करने का अनुरोध किया था। तदनुसार, 18 राज्‍य सरकारों और 1 संघ शासित प्रदेश ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम कर दिया है।

\*\*\*\*\*